बिहार विधान परिषद

(बिहार विधान परिषद् का 194वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

17 मार्च 2020

[ऊर्जा - उद्योग - स्वास्थ्य - अल्पसंख्यक कल्याण - गन्ना उद्योग - संसदीय कार्य - विधि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग].

Total Short Notice Question- 13

अपडेट कराने पर विचार

*112 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में मरीज और उनके परिजनों को परामर्श देने, डाक्टरों, नर्स से लेकर टेक्निकल स्टाफ तक की संख्या, रोगियों के शिकायत निदान के लिए प्रबंधन की ओर से दी जाने वाली सुविधा आदि की जानकारी, नागरिक घोषणा पत्र (सिटीजन चार्टर) में दर्ज कराने का दायित्व मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक और प्रिंसिपल को सौंपा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के बड़े अस्पताल पी.एम.सी.एच. एवं एन.एम.सी.एच. में अक्सर मरीजों के परिजनों की शिकायत अखबरों में छपती रहती है कि प्रतिदिन सुविधाओं से संबंधित सिटीजन चार्टर को अपडेट नहीं किया जाता है, जिससे भर्ती मरीजों के परिजनों को इधर-उधर भटकना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रतिदिन सिटीजन चार्टर को अपडेट कराने के लिए कौन-सा कदम उठाने पर विचार कर रही है, यदि नहीं तो क्यों ?

एनीमिया रोग से बचाव

***113 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-
क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतालाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 15 से 19 वर्ष की 54 प्रतिशत लड़कियां एनीमिया की शिकार हैं तथा दूध पिलाने वाली 58 प्रतिशत माताओं में एनीमिया है;

(ख) क्या यह सही है कि एनीमिया से शिकार ज्यादातर लड़कियां शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती हैं और मां बनने पर उनकी संतानें भी कुपोषण का शिकार हो जाती हैं;

(ग) क्या यह सी है कि मातृ मृत्यु का बड़ा कारण एनीमिया है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इस एनीमिया चक्र को गतिशून्य बनाने के लिए सरकार कौन-सा कारगर उपाय कर रही हैं ?

स्वच्छ पानी देने का विचार

***114 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

Will the **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** be pleased to state:-
क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले के लगभग 26 लाख आबादी को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्तर पर 30 हजार 694 सरकारी चापाकल लगाए गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अभी भी 7 लाख मकान में अधिकांश गरीब परिवार 30-40 फीट पाइप लगाकर चापाकल से पानी पी रहे हैं जो दूषित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गरीब परिवारों को चिन्हित कर स्वच्छ पानी देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

राष्ट्रीय आरोग्य निधि का लाभ

***115 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-
क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बीपीएल) को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना में इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की मदद मिलती है जबकि आयुष्मान भारत योजना में सिर्फ 5 लाख रुपये का इलाज कराने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि एप्लास्टिक, एनीमिया नामक बीमारी से पीडि़त रोगी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी जिसमें करीब 12 लाख रुपये का खर्च आता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बतलाएगी कि आयुष्मान भारत योजना वाले को राष्ट्रीय आरोग्य निधि का लाभ क्यों नहीं मिलेगा?

फेको मशीन की व्यवस्था

***116 श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):**

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-
क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में चार महीने से आंखों का ऑपरेशन बंद है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल का फेको मशीन का हैंडपीस खराब पड़ा है जिसकी कीमत सवा तीन लाख रुपये है;

(ग) क्या यह सही है कि सवा तीन लाख रुपये के उपकरण नहीं बदलने के कारण तीस लाख की मशीन बेकार पड़ी है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो मरीजों की परेशानी के मद्दे नजर सरकार उक्त अस्पताल के फेको मशीन को शीघ्र चालू करने हेतु कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

दोषियों पर कार्रवाई

***117 श्री सतीश कुमार (विधान सभा):**

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले में स्वास्थ्य विभाग में कई वर्षों से फर्जी बहाली पटना स्वास्थ्य विभाग से डाक के द्वारा सीएस कार्यालय को भेजा जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि हाल ही तीन फर्जी बहाली पत्र हरसिद्धि चिकित्सा प्रभारी को दिया गया जिसमें राजेश कुमार, संजीत कुमार व मो. मोस्ताफा का नाम शामिल है तथा 16 ए.ए.एन.एम. तथा एक माह पहले कार्यरत नर्स डेजी सिन्हा का जाली प्रमाण पत्र पाया है जिन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाएगी कि पूर्वी चम्पारण जिले के स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा रैकेट तथा पटना स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत है जिससे प्रमाणित होता है कि सीएस कार्यालय के द्वारा जांच हेतु पटना स्वास्थ्य विभाग पत्र भेजा जाता है परंतु कोई जवाब या कार्रवाई नहीं की जाता है, क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जर्जर विद्युत तार बदलने की व्यवस्था

*118 **श्री राजन कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

Will the **ऊर्जा** be pleased to state:-

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के नगर परिषद् शहरी इलाके में बिजली का तार जर्जर हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय में जर्जर तार होने के कारण कोई गंभीर घटना होने का भय बना रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार औरंगाबाद सदर में जर्जर तार कबतक बदलना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

राशि उपलब्ध

*119 **श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

Will the **उद्योग** be pleased to state:-

क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग के द्वारा वर्ष 2017 में बिहार स्टार्ट अप

नीति, 2017 बनाई गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नीति के तहत प्राप्त आवेदनों, उनके इन्क्यूबेशन, प्रमाणीकरण एवं स्टार्ट अप को उपलब्ध कराये गये सीड फंड की प्रगति सुनिश्चित कराने का काम विभाग के द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि स्टार्ट अप के लिए अबतक कुल 9672 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें मात्र 4961 को विभिन्न इन्क्यूबेटर के साथ इन्क्यूबेशन हेतु संबद्ध किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि 9672 आवेदनों में मात्र 154 स्टार्ट अप की अनुशंसा अभी तक इन्क्यूबेटर के द्वारा की गई है जिनमें मात्र 60 आवेदकों को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्टार्ट अप के लिए दिए गए सभी आवेदकों को राशि उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अस्पताल का निर्माण

*120 **श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-
क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत 20 फरवरी, 1993 को अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि अनुमंडलीय अस्पताल नहीं होने के कारण संसाधन के अभाव में दम तोड़ते बीमार मरीजों को मधुबनी या दरभंगा रेफर कर दिया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि बेनीपट्टी को अनुमंडल बने 36 वर्ष हो गए और क्षेत्र के लोगों को आशा थी कि अनुमंडल अस्पताल की सुविधा मिल पाएगी, लेकिन अस्पताल का निर्माण तो हुआ नहीं और 25 वर्ष पूर्व लगा शिलापट्ट भी क्षतिग्रस्त हो कर टूट चुका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण कराना चाहती है ?

वेतन का भुगतान

*121 **श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

Will the **गन्ना उद्योग** be pleased to state:-
क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिले में स्थित तिरुपति शुगर मिल लिमिटेड, बगहा मिल प्रबंधन के जिम्मे शुगर मिल मजदूरों का वेतन माह मार्च 2003, जनवरी 2004, फरवरी 2004 का बकाया है;

(ख) क्या यह सही है कि तिरुपति शुगर मिल लिमिटेड, बगहा सेवानिवृत्त हुए करीब 46 मजदूरों का ग्रेच्युटी का रुपया का भुगतान पूर्व प्रबंधन से ही बकाया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बगहा तिरुपति शुगर मिल प्रबंधन से मिल मजदूरों को बकाये वेतन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान दिलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

पम्प ऑपरेटर की व्यवस्था

***122 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

Will the **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** be pleased to state:-
क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के ग्राम बीथो शरीफ में दरगाह के पास राज्य सरकार द्वारा बनाये गये जल मीनार से गांव के सैकड़ों घरों में मुफ्त पानी मुहैया कराया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि जल मीनार में लगी मशीन प्रायः खराब रहती है, जिसकी देखरेख तथा सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, यहां तक की चहारदवारी भी असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दी गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा आज तक उसके प्रबंधन के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जल मीनार की सुरक्षा तथा उसकी देखरेख के लिए एक पम्प ऑपरेटर की व्यवस्था कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अनियमितता के विरुद्ध कार्रवाई

***123 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-
क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा आई.जी.आई.एम.एस., पटना

में अनियमितता के विरुद्ध दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी.-23575/2018 को निष्पादित करते हुए संबंधित पदाधिकारी को तीन महीने के अंदर नियमानुकूल निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त निर्देश के आलोक में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च न्यायालय द्वारा अनियमितता के विरुद्ध दिए गए निर्देश को अक्षरशः लागू कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

खर्चा वहन करने पर विचार

*124 **श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

Will the **स्वास्थ्य** be pleased to state:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि प्रसव के दौरान सूई लगाने एवं नवजात का कार्ड बनाने तथा प्रसव संबंधी सुविधा मुहैया कराने हेतु अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जच्चा—बच्चा के परिवार वालों से पैसे लिए जाते हैं, तथा दवाइयां बाहर से क्रय करने का दबाव बनाया जाता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य में प्रसव के दौरान सूई लगाने, दवा क्रय करने एवं कार्ड बनाने तथा अन्य खर्चों का वहन सरकार करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?